

मस(बारण

EXTRAORDINARY

भाग Π —लण्ड 3—उपलण्ड (\ddot{u})

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

310]

मई विल्ली, मंग नवार, द्मागरन 25, 1970/भाव 3, 1892

No. 3101

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 1970/BHADRA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलम के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment;

ORDER

New Delhi, the 25th August 1970

- S.O. 2814.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed exists between the bargemen—represented by:-
 - (1) Calcutta Port Sramik Union, Calcutta-23.
 - (2) Calcutta Port and Dock Workers Union. Calcutta-23.
 (3) Calcutta Dock Workers Union, Calcutta-23.
 (4) West Bengal Dock Mazdoor Union, Calcutta-23

 - (5) Calcutta Boatmen's Union, Calcutta-23.

and the owners of barges, lighters and boats—represented by:--

- The Bengal River Transport Association, Calcutta-1.
- (2) The Calcutts River Transport Association, Calcutta-1.
- (3) M/s. Fraser & Co., Calcutta-1.

plying to, fro and within the Port of Calcutta and that the dispute involves a question of national importance;

And, whereas the Central Government is of opinion that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7B and subsection (1A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Tribunal at Calcutta of which Shri B N. Baneriee shall be the Presiding Officer and refers the said dispute to the said National Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers as accepted by the Central Government in their Resolution No. WB-21(7)/69, dated the 28th March, 1970, are applicable to the bargemen in the matter of wages and allowances? If not, to what other relief with regard to wages and allowances are they entitled?"

[No. 72/10/70-P&D-Vol.II.]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार ग्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रीर रोजगार विभाग)

द्मावेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त 1970

का० भा० 2814.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में विनि-विष्ट विषयों के बारे में बार्जमेंनों, जिनका प्रतिनिधित्व :--

- (1) कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, कलकत्ता~23
- (2) कलकत्ता पोर्ट एंड डांक वर्कर्स युनियन, कलकत्ता-23
- (3) कतकत्ता डाक वर्कसं यूनियन, कलकत्ता-23
- (4) पश्चिमी बंगाल डाक मजदूर यूनियन, कलकता-23
- (5) कलकता बोटमैन्स यूनियन , कलकता-23

करते है और बार्जो, माल बोटों श्रौर नोकाश्रों के जो कलकत्ता फ्तन को, उससे श्रौर उसके भोतर चलते है स्वामियों के, जिनका प्रतिनिधित्व :--

- (1) दि बंगाल रीवर ट्रासपोर्ट एसोसिएसन, कलकता -1
- (2) दि कलकत्ता रीवर ट्रास्पोर्ट एसोमिएशन, कलकत्ता-1
- (3) मैंसर्स फेजर एण्ड कम्पनी, कलकत्ता-1

करते है, बीच एक श्रौद्योगिक विवाद विश्वमान है श्रौर कि इस विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न सन्तर्वेलित है ।

भौर यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस विवाद का न्यायनिर्णयन किसी राष्ट्रीय श्रधिकरण द्वररा किया जाना चाहिए

मतः, मन, भौधोगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा-7(ख) भौर धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा करकत्ते में एक राष्ट्रीय श्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रधिकारी श्री बी० एन० बनर्जी होंगे और उक्त विवाद को उक्त राष्ट्रीय श्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

श्रनुसूची

"क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रपने संकल्प सं० डब्ल्यू बी-21 (7)/69 तारीख 28 मार्च, 1970 में यथा प्रतिगृहित केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की पत्तन श्रोर डाक कर्म कारों के लिए की गई सिफा-रिशों मजदूरी श्रीर भतों के मामले में बार्ज मेनों को लागू होती हैं? यदि नहीं, तो वे मजदूरी श्रीर भत्तों के सम्बन्ध में कीन से श्रन्य श्रनुतीष के हकदार हैं?"

[स॰ 72/10/70—पी॰ एण्ड स्री जिल्द-II]

टी० एस० संकरन, संयुक्त सचिव (एस)।